

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

न्यायाधीश एस. पी. गोयल और जी. सी. मित्तल के समक्ष

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स -आवेदक।

बनाम

आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़ -उत्तरदाता।

आयकर संदर्भ सं. 30 सन् 1978

नवंबर 22,1985.

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित आयकर (1961 का XLII)-धारा 271 (1) (क) और 275-आय विवरणी दाखिल करने में विलम्ब-दंड कार्यवाही प्रारंभ की गई-न करने के लिए उचित कारण का अभाव। समय पर विवरणी प्रस्तुत करना-ऐसी अनुपस्थिति को साबित करने की जिम्मेदारी-क्या यह निर्धारिती पर निर्भर करता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1) में यह उपबंध किया गया है कि यदि आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील) अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान इस बात से संतुष्ट हैं कि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहा है तो वह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति उस धारा के उपबंधों के अनुसार निर्धारित की जाने वाली रकम का दंड के रूप में संदाय करेगा। अतः इससे पहले कि जुर्माना लगाया जा सके, संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि निर्धारिती बिना किसी उचित कारण के विवरणी दाखिल करने में विफल रहा है। जाहिर है, जब तक कोई कारण नहीं दिखाया जाता है, तब तक इसकी तर्कसंगतता का आकलन कैसे किया जा सकता है। उचित कारण निर्धारिती के व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर होने के कारण उसे यह दिखाना होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि शुरु में यह दिखाना राजस्व के लिए होगा कि विफलता बिना किसी उचित कारण के थी और यह केवल तभी होगा जब निर्धारिती ने कारण दिखाया हो कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसकी तर्कसंगतता या अन्यथा के बारे में राय बनाई जा सकती है। के प्रति दायित्व। निर्धारित समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत न करने की विफलता पर जुर्माना नामक अतिरिक्त कर का अधिरोपण तुरंत उत्पन्न होगा। वास्तविक अधिरोपण को तब तक स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि निर्धारण प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि विफलता बिना किसी उचित कारण के थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह दिखाना राजस्व का काम है कि विफलता बिना किसी उचित कारण के हुई थी। इसके विपरीत, इसका केवल यह अर्थ है कि निर्धारिती की ओर से निर्धारित अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफलता पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि वह यह दिखाने में सक्षम है कि ऐसा न करने का पर्याप्त कारण था। दूसरे शब्दों में, हालांकि निर्धारिती निर्धारित समय के भीतर विवरणी दाखिल नहीं करने के लिए जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करने के लिए एक अच्छा कारण दिखाने में सक्षम है तो वह इसे रोक सकता है।

अतः यह दिखाने के लिए कि निर्धारिती के पास निर्धारित समय के भीतर विवरणी दाखिल नहीं करने के लिए उचित कारण था, प्रमाण का भार उसके ऊपर होगा और उसे प्रस्तुत करने पर यह निर्धारण प्राधिकारी के लिए होगा कि वह एक राय तैयार करे कि क्या कोई अच्छा कारण था या विफलता उचित कारण के बिना थी।

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

I.T.A. में 4 अगस्त, 1977 के अधिकरण के आदेश से उद्भूत विधि के निम्नलिखित प्रश्नों पर, चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की राय के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण (चंडीगढ़ न्यायपीठ) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256 (1) के अधीन निर्देश। नं. 1976-76 का 28: —

(i) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, अधिकरण विधि में यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि धारा 275 प्रक्रियात्मक प्रकृति की थी और आगे यह अभिनिर्धारित करने में कि धारा 275 के संशोधित उपबंधों को उचित रूप से लागू किया गया था और इस प्रकार दंड कार्यवाहियों को केवल समय से वर्जित नहीं किया गया था?

(ii) क्या अधिकरण ने उचित रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि आय-कर अधिनियम, जैसा कि किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को संशोधित किया गया है, उस वर्ष के निर्धारण पर लागू होगा, लेकिन उस वर्ष की दंड कार्यवाहियों पर नहीं?

(हाय) क्या अधिकरण का यह अभिनिर्धारित करना कानूनी रूप से सही था कि राजस्व पर यह साबित करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि विलंब बिना किसी उचित कारण के किया गया था।

आर ए। नं. 1977-78 का 71 I.T.A. से बाहर निकल रहा है। नं. 28 सन् 1976-77)

(Assessment Year: 1966-67).

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंदरजीत अहलूवालिया के साथ अधिवक्ता बलवंत सिंह गुप्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता अजय मित्तल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान।

आदेश

न्यायाधीश एसपी गोयल

1. निर्धारिती एक पंजीकृत साझेदारी संस्था है। इसका रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 जून, 1966 थी, लेकिन इसे 13 अक्टूबर, 1970 को दाखिल किया गया। रुपये की कुल आय पर मूल्यांकन 31 अगस्त, 1971 को पूरा किया गया। 1,46,170. रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 271(1)(ए) के तहत दंड की कार्यवाही, मूल्यांकन पूरा होने पर एक साथ शुरू की गई थी। निर्धारिती ने अपने उत्तर में विभिन्न स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए जो मूल्यांकन प्राधिकारी को पसंद नहीं आए। निर्धारिती ने यह भी दलील दी कि डिफॉल्ट 13 अक्टूबर, 1970 को पूरा हो गया था, जब रिटर्न दाखिल किया गया था और धारा 275 के प्रावधानों के तहत, जैसा कि तब था, जुर्माना की कार्यवाही तारीख से दो साल की अवधि के भीतर पूरी होनी चाहिए थी। मूल्यांकन कार्यवाही का समापन. मूल्यांकन प्राधिकारी ने इस तर्क को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा 1 अप्रैल, 1971 से संशोधित धारा 275 के प्रावधान लागू थे और केवल छह महीने बीते थे। राजस्व द्वारा दायर अपील में ट्रिब्यूनल द्वारा आदेश पारित किया गया था, निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना आदेश पारित किया जा रहा था। अपीलीय सहायक आयुक्त के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के समक्ष असफल होने पर, निर्धारिती को अधिनियम की धारा 256(1) के तहत निम्नलिखित तीन प्रश्न इस अदालत में भेजे गए:

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

" 1. क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि धारा 275 प्रकृति में प्रक्रियात्मक थी और आगे यह भी मानते हुए कि धारा 275 के संशोधित प्रावधानों को सही तरीके से लागू किया गया था और इस प्रकार जुर्माना लगाया गया था कार्यवाही समय-बाधित नहीं थी?

2. क्या ट्रिब्यूनल ने सही माना है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अप्रैल के 1 दिन को संशोधित आयकर अधिनियम उस वर्ष के मूल्यांकन पर लागू होगा, लेकिन उस वर्ष की जुर्माना कार्यवाही पर नहीं?

3. क्या ट्रिब्यूनल का यह मानना सही था कि यह साबित करने की जिम्मेदारी राजस्व पर नहीं है कि देरी बिना किसी उचित कारण के हुई थी? "

2. पहले दो प्रश्न जो एक ही क्षेत्र को कवर करते हैं, सीआईटी बनाम साधु राम [1981] 127 आईटीआर 517 में इस अदालत के फैसले से समाप्त हो गए हैं, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि एक प्रक्रियात्मक कानून होने के कारण सीमा का कानून हमेशा पूर्वव्यापी प्रभाव रखता है जब तक कि संशोधित कानून अन्यथा प्रदान न करे। इसे आगे आयोजित किया गया (पृष्ठ 520 पर):

" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 275 , जो समय-सीमा प्रदान करती है जिसके भीतर जुर्माना लगाने की कार्यवाही पूरी की जानी थी, 1 अप्रैल, 1971 से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम , 1970 द्वारा संशोधित किया गया था। , और इसके संशोधन के बाद जुर्माना कार्यवाही उस वित्तीय वर्ष के पूरा होने के दो साल के भीतर पूरी की जा सकती है जिसमें जुर्माना कार्यवाही शुरू की गई थी, क्योंकि यह धारा सीमा के नियम का प्रतीक है जो प्रक्रियात्मक है और इसलिए, जुर्माना को नियंत्रित करेगी अधिरोपण के समय कार्यवाही। "

3. तदनुसार, उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक, अर्थात् निर्धारिती के विरुद्ध और राजस्व के पक्ष में दिया जाता है।

4. प्रश्न संख्या 3 पर, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यह साबित करने का दायित्व कि निर्धारित अवधि के भीतर रिटर्न प्रस्तुत न करने का कोई उचित कारण नहीं था, राजस्व पर था और ट्रिब्यूनल का दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं था। इस प्रस्ताव के लिए निर्भरता को अतिरिक्त में गुजरात उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर रखा गया था। सीआईटी बनाम आईएम पटेल एंड कंपनी । [1977] 107 आईटीआर 214। जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेद से स्पष्ट होगा, उचित कारण की अनुपस्थिति को साबित करने का बोझ राजस्व पर था, यह मानने के लिए पूर्ण पीठ के फैसले का अनुपात यह था कि जुर्माना लगाने की कार्यवाही अर्ध थी -आपराधिक और इसलिए, अभियोजन पक्ष को अपराध के सभी तत्वों को साबित करना था (हेडनोट):

" आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1) के तहत जो जुर्माना लगाया जा सकता है , वह अपमानजनक या धोखाधड़ी वाले करदाताओं पर लगाया जाना है। यह एक अर्ध-आपराधिक कार्यवाही है और यह धारा इस अर्थ में दंडात्मक है कि इसके परिणाम एक प्रभावी निवारक होने का इरादा है जो उन प्रथाओं पर रोक लगाएगा जिन्हें विधानमंडल सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है। जब भी कोई कानून किसी अपराध को परिभाषित करता है और उसके लिए दंड का प्रावधान करता है, तो अभियोजन पक्ष को अपराध के सभी तत्वों को साबित करना होता है अधिनियम की धारा 271(1)(ए) के तहत जुर्माना कार्यवाही में , निर्धारिती जिस पर जुर्माना लगाने की मांग की गई है वह एक आपराधिक मुकदमे में आरोपी की स्थिति में है और इसलिए, अपराध की सभी सामग्री जो जुर्माना लगाया जा सकता है उसे राजस्व द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। यह

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

इस पहलू से है कि किसी को इस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या धारा 27 एल(1)(ए) में 'उचित कारण के बिना विफलता' शब्द अपराध का एक घटक है या नहीं। धारा की शब्दावली और धारा 271(1)(ए) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, सबसे पहले यह स्पष्ट है कि रिटर्न दाखिल करने में विफलता उचित कारण के साथ या उचित कारण के बिना हो सकती है, लेकिन वह अपराध जिसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा में निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने में उचित कारण के बिना विफलता असंभव है और इसलिए, यह राजस्व के लिए एक घटक के रूप में स्थापित करना है कि विशेष मामले में विफलता उचित कारण के बिना थी। एक बार जब विभाग ने उस प्रारंभिक बोझ का निर्वहन कर दिया है, तो यह निर्धारिती के लिए होगा कि वह दिखाए कि समय पर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए उसकी ओर से उचित कारण था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अंतर्निहित सिद्धांतों पर, चूंकि उचित कारण का गठन करने वाले तथ्य विशेष रूप से निर्धारिती के ज्ञान के भीतर हैं, यह उन तथ्यों को स्थापित करने के लिए उसका काम होगा, लेकिन विभाग को पहले साक्ष्य का नेतृत्व करना होगा जो दिखाने के लिए जाएगा प्रथम दृष्टया, कि निर्धारिती के पास निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने का कोई उचित कारण नहीं था। बिना कुछ और बताए समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफलता मात्र से करदाता पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। केवल निर्धारिती की ओर से स्पष्टीकरण का मिथ्या होना इस धारा के तहत अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आयकर आयुक्त बनाम गोकुलदास हरिवल्लभदास [1958] 34 आईटीआर 98 और आयकर आयुक्त बनाम अनवर अली [1970] 76 आईटीआर 696 मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह है यह स्पष्ट है कि अपराध के सभी तत्वों को साबित करने का भार विभाग पर है और यदि विभाग केवल यह इंगित करने के अलावा कि समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता थी, बिंदु पर कोई सबूत देने में विफल रहता है, तो विभाग अब तक विफल रहेगा। के तहत जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है धारा 271(1)(ए) का संबंध है... इसलिए: (1) अधिनियम की धारा 271(3)(ए) के तहत, प्रस्तुत करने में 'उचित कारण के बिना' विफलता, वापसी अपराध का एक घटक है। (2) धारा 271(1)(ए) उन मामलों में दंड का प्रावधान करती है जहां निर्धारिती ने या तो जानबूझकर कानून की अवहेलना की है या आचरण का दोषी है, अपमानजनक या बेईमान है, या अपने दायित्व के प्रति सचेत उपेक्षा में काम किया है। (3) विभाग पर यह कानूनी बोझ है कि वह कुछ सबूत पेश करके यह स्थापित करे कि प्रथम दृष्टया निर्धारिती बिना किसी उचित कारण के धारा 271(1)(ए) के साथ पढ़ी गई अन्य प्रासंगिक धाराओं में निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा है। उस अनुभाग में, एक बार जब यह प्रारंभिक बोझ, जो मामूली हो सकता है, विभाग द्वारा हटा दिया गया है, तो यह निर्धारिती के लिए है, जैसा कि एक नागरिक मामले में, संभावनाओं के संतुलन पर, यह दिखाना है कि उसके पास समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने में विफल रहने का उचित कारण था। निर्दिष्ट. (4) केवल निर्धारिती द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की मिथ्याता विभाग को जुर्माना लगाने के समय निर्धारिती के खिलाफ अपना मामला स्थापित करने में मदद नहीं कर सकती है।"

5. हालाँकि, इस पूर्ण पीठ के दृष्टिकोण और अनुपात को सीआईटी बनाम पत्रम दास राजा राम बेरी [1981] 132 आईटीआर 671 मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ का समर्थन नहीं मिला और निम्नलिखित शर्तों में इस पर असहमति जताई गई (मुख्य टिप्पणी):

"मेन्स री का सिद्धांत जो संक्षेप में आपराधिक कानून के दायरे से संबंधित है, आम तौर पर कर कानूनों के तहत दंड लगाने के लिए आकर्षित नहीं किया जाएगा जो संक्षेप में राजस्व के त्वरित संग्रह के लिए जबरदस्त नागरिक प्रतिबंध और उपाय हैं। सीए अब्राहम बनाम में। आईटीओ [1960] 41 आईटीआर 425 (एससी), सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने दंड को

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

अतिरिक्त कर का भुगतान करने के दायित्व के रूप में देखा और कर दायित्व के मूल्यांकन के लिए मशीनरी के हिस्से के रूप में दंड कार्यवाही को माना। कोई भी सार्वभौमिक या व्यापक सिद्धांत जो पुरुषों का मानना है या किसी भी कर संबंधी क़ानून में कोई भी जुर्माना लगाने से पहले दोषी दिमाग एक आवश्यक पूर्व-आवश्यकता है, जिसे अब आरएस जोशी बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की बेंच ने आधिकारिक और निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया है। [1977] 40 एसटीसी 497. आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि अधिनियम पहले निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने का कर्तव्य निर्धारित करता है और फिर उस वैधानिक दायित्व को लागू करने के लिए तीन अलग-अलग मंजूरी देता है। ये हैं, धारा 139 के तहत ब्याज लगाना, धारा 271(1)(ए) के तहत उचित कारण के बिना देरी होने पर जुर्माना लगाना, और धारा 276 सीसी के तहत निर्धारिती को दोषी ठहराना और सजा देना। यदि यह साबित हो जाए कि यह जानबूझकर किया गया था तो इसे अपराध माना जाएगा। निर्धारित समय से परे रिटर्न दाखिल न करने या रिटर्न दाखिल न करने की तीन अलग-अलग और अलग-अलग डिग्री हैं और क़ानून स्पष्ट रूप से तीन तरीकों के बीच सभी चरणों में अंतर रखता है। जबकि विधानमंडल उचित कारण के अभाव के बारे में संतुष्टि तक पहुंचने पर केवल वित्तीय जुर्माना लगाने से संतुष्ट है, इसने निर्धारित समय में रिटर्न प्रस्तुत करने में जानबूझकर विफलता की उपस्थिति को दंडनीय अपराध बनाने के लिए न्यूनतम कारावास के साथ जुर्माना भी जोड़ा है। धारा 271(1)(ए) में उल्लिखित 'दंड' शब्द और धारा 276 सीसी द्वारा प्रदत्त कठोर दंडों के बीच का अंतर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम की धारा 271(1)(ए) (आई) के संदर्भ से संकेत मिलता है कि विधायिका ने स्वयं इस 'जुर्माने' को कर की राशि, यदि कोई हो, के अतिरिक्त के रूप में देखा है, जो निर्धारिती द्वारा देय है और इसकी गणना की जाती है। निर्धारित कर की राशि के संबंध में, इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि यहां लगाया गया जुर्माना एक तरह से कर से संबंधित है और मूल्यांकन कार्यवाही का हिस्सा है। धारा 276CC के तहत क्या लगाया जाता है अधिनियम की प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। उसमें की कार्यवाही न तो मूल्यांकन कार्यवाही का हिस्सा है और न ही जुर्माना सीधे लगाए जाने वाले कर की राशि के अनुपात में है। इसके खंड (i) और (ii) के तहत अपराधी को कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे क्रमशः सात साल या तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है। जबकि जुर्माना लगाने के लिए, उचित कारण की अनुपस्थिति दिखानी होगी, सजा देने के लिए, जानबूझकर विफलता स्थापित करनी होगी और, आपराधिक कानून के एक स्थापित सिद्धांत के रूप में, ऐसा करने का बोझ अभियोजन पर निर्भर करता है। इच्छाशक्ति निश्चित रूप से अपराध के तत्व को सामने लाती है और इस प्रकार आपराधिक मनःस्थिति की आवश्यकता होती है, लेकिन उचित कारण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण हो सकती है और उससे बहुत दूर हो सकती है। धारा 271 का शीर्षक स्वयं उन विषयों को वर्गीकृत करता है जिनसे यह संबंधित है: (i) रिटर्न प्रस्तुत करने में विफलता; (ii) नोटिस का अनुपालन करने में विफलता; और (iii) आय छिपाना, आदि। इससे, यह स्पष्ट है कि धारा 271 तीन अलग-अलग स्थितियों से निपटने का प्रयास करती है। यह समान रूप से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीन स्थितियों को अधिनियम की धारा 271 की उप-धारा (आई) के खंड (ए), (बी) और (सी) में अलग-अलग और स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। इस प्रकार, भले ही ऊपर उल्लिखित तीन प्रकार के मामलों को एक साथ समूहीकृत किया गया है, यह अनुभाग उनमें से प्रत्येक को अलग-अलग और विशिष्ट रूप से मानता है। प्रासंगिक खंडों के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा विविध है और जबकि 'उचित कारण के बिना' शब्द खंड (ए) और (बी) में आते हैं, वे खंड (सी) में उनकी अनुपस्थिति से विशिष्ट हैं। इसके अलावा, इन धाराओं में अपराध की तीन श्रेणियों पर अलग से विचार किया गया है। उप-खंड (i) जो खंड (ए) में उल्लिखित कर अपराध को संदर्भित करता है, कम से कम भारी दंड का प्रावधान करता है। उप-खंड (ii), जो खंड (बी) के मामलों को संदर्भित करता है, थोड़ा भारी दंड लगाता है, जबकि उप-खंड (iii), जो खंड (सी) के मामलों को संदर्भित करता

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

है, उच्चतम दंड प्रदान करता है। यदि इरादा इन सभी अपराधों को समान रूप से व्यवहार करने का था, तो स्पष्ट रूप से संसद को दंड के इन तीन अलग-अलग आदेशों को निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए, यह इस प्रकार है कि समान विचार अधिनियम की धारा 271(1) के खंड (ए), (बी) और (सी) पर लागू नहीं हो सकते हैं और न ही लागू होते हैं। इसलिए, आयकर अधिनियम की व्यापक योजना, धारा 271 (एलजे(ए)) की विशिष्ट भाषा और उदाहरणों के महत्व के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि आपराधिक मनःस्थिति का सिद्धांत धारा के तहत दंड की कार्यवाही के लिए आकर्षित नहीं है। 271(1)(ए)। इसके तहत एकमात्र आवश्यकता कर चूक के लिए उचित कारण की उपस्थिति या अनुपस्थिति है। कानून की जानबूझकर अवहेलना या अपमानजनक आचरण या बेईमान इरादे या वैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत उपेक्षा में कार्य करने की आवश्यकता धारा के तहत अनुचित है 271(1)(ए)।"

6. ट्रिब्यूनल ने अपने दृष्टिकोण के लिए तीन अन्य उच्च न्यायालयों, यानी केरल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की पूर्ण पीठ के फैसलों पर भी भरोसा किया: (1) सीआईटी बनाम गुजरात त्रावणकोर एजेंसी [1976] 103 आईटीआर 149 (केर); (2) सीआईटी बनाम गंगाराम चापोलिया [1976] 103 आईटीआर 613 (उड़ीसा) और (3) अतिरिक्त। सीआईटी बनाम दर्गापंडारीनाथ तुलजय्या एंड कंपनी। [1977] क्रमशः 107 आईटीआर 850 (एपी) [एफबी]।

7. आईएम पटेल के मामले में निर्णय का अनुपात [1977] 107 आईटीआर 214 (गुजरात) [एफबी] इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा स्पष्ट रूप से असहमति व्यक्त की गई है लेकिन सबूत के बोझ के सवाल पर सीधे चर्चा नहीं की गई थी। इसलिए इस एंगल से भी मामले की जांच जरूरी है। धारा 271(1) में प्रावधान है कि यदि आयकर अधिकारी या अपीलीय सहायक आयुक्त या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान संतुष्ट हैं कि कोई भी व्यक्ति उचित कारण के बिना रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहा है, तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में उस धारा के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन की जाने वाली राशि का भुगतान करेगा। इसलिए, जुर्माना लगाने से पहले, संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट होना होगा कि निर्धारित बिना किसी उचित कारण के रिटर्न दाखिल करने में विफल रहा है। जाहिर है जब तक कोई कारण नहीं बताया जाता, उसकी तर्कसंगतता का आकलन कैसे किया जा सकता है। आईएम पटेल के मामले में दीवान सीजे [1977] 107 आईटीआर 214 (गुजरात) [एफबी] ने देखा है कि उचित कारण निर्धारित के व्यक्तिगत ज्ञान के भीतर है, इसलिए उसे इसे दिखाना होगा। इन परिस्थितियों में, यह कैसे कहा जा सकता है कि शुरुआत में यह राजस्व को दिखाना होगा कि विफलता बिना किसी उचित कारण के थी और यह केवल तभी होगा जब निर्धारित ने कारण दिखाया है कि इसके बारे में संबंधित प्राधिकारी द्वारा राय बनाई जा सकती है तर्कसंगतता या अन्यथा। निर्धारित समय के भीतर रिटर्न जमा न करने पर अतिरिक्त कर, जिसे जुर्माना कहा जाता है, लगाने की देनदारी तुरंत उत्पन्न होगी। वास्तविक अधिरोपण तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है जब तक कि मूल्यांकन प्राधिकारी यह निष्कर्ष नहीं निकाल लेता कि विफलता बिना किसी उचित कारण के थी। इसका मतलब यह नहीं है कि यह दिखाना राजस्व का काम है कि विफलता बिना किसी उचित कारण के थी। इसके विपरीत, इसका मतलब केवल यह है कि निर्धारित अवधि के भीतर रिटर्न प्रस्तुत करने में निर्धारित की विफलता पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा यदि वह यह दिखाने में सक्षम है कि ऐसा नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था। दूसरे शब्दों में, यद्यपि निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर निर्धारित जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करने का कोई अच्छा कारण दिखाने में सक्षम है तो वह इससे बच सकता है। इसलिए, यह दिखाने के लिए कि निर्धारित के पास निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल न करने का उचित कारण था, सबूत का भार उस पर होगा और उस मामले को प्रस्तुत करने पर, यह आकलन प्राधिकारी के लिए एक राय बनाने के लिए होगा कि क्या

हरियाणा आयरन और स्टील रोलिंग मिल्स बनाम आय कर आयुक्त, हरियाणा और चंडीगढ़

वहां एक अच्छा कारण था या असफलता बिना किसी उचित कारण के थी। तदनुसार, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर भी सकारात्मक दिया गया है, अर्थात् राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध। कोई लागत नहीं।

जीसी मितल, जे.

8. मैं सहमत हूं.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

अनुराग यादव

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

Trainee Judicial Officer

नारनौल, हरियाणा